

राजस्थान सरकार

四

नगरीय विकास आवारान एवं रखायत शारान तिगांग

क्रमांक प.३(५४)नविति / ३ / २०११

जयपुर दिनांक : 18 अक्टूबर 20

1. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण।
 2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
 3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
 4. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
 5. संघिय, नगर विकास न्यास, (समस्त) राजस्थान।
 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, (समस्त) राजस्थान;
 7. वरिष्ठ नगर नियोजक, (समस्त) राजस्थान।
 8. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
 9. अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :- "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" आयोजित करने वाले

राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में आगामी 'प्रशासन शहरों के संग अभियान' चलाए जाने के संबंध में समसंख्यक परिपत्र के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। उक्त निर्देशों के बिन्दु संख्या 27 में बताया गया है कि परिपत्र के बिन्दु संख्या 1(vi), 1(viii), 1(ix), 1(x), एवं 11 पूर वर्धित शिथिलताओं के लिए वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

जारी किये जायेंगे। अब इस क्रम में वित्त विभाग द्वारा भी (i) अधिसूचना कमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स, 12-72 दिनांक 18.10.2012, (ii) अधिसूचना कमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12-73 दिनांक 18.10.2012, (iii) अधिसूचना कमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12-74 दिनांक 18.10.2012 एवं (iv), अधिसूचना कमांक एफ 2(70)एफ.डी./टैक्स/12-75 दिनांक 18.10.2012 जारी कर दी गयी है जिनकी प्रतियो संलग्न है। वित्त विभाग की इन अधिसूचनाओं के अनुरूप इस विभाग के संदर्भित परिपत्र में वर्णित किये गये निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही निम्न प्रकार से की जानी है:-

- कार से की जानी है :-

 1. दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की योजनाओं के हस्तानात्तरित मुख्यण्डों के नियमन की प्रक्रिया, नियमन शुल्क तथा पंजीयन शुल्क :-

संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1(vi) के अन्तर्गत बताया गया है कि जिन घटकों को विभाग 30.9.2012 तक जितनी बार इकरारनामा किया गया है उनका नगरीय निकायों द्वारा नियमन किया जायेगा। अंजीष्टहाइकरारनामा तथा कब्जे की स्थिति में केवल प्रीभियम राशि वसूल कर नियमन किया जायेगा तथा अपंजीकृत इकरारनामे एवं कब्जे की स्थिति में 10 लं प्रति वर्गज राशि के साथ प्रीभियम राशि ली जाकर अभिन्न केता के पक्ष में नियमन किया जायेगा।

(3)

वित्त विभाग ने ऐसे मामलों में मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की गणना / देयता के संबंध में अधिसूचना क्रमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12-72 दिनांक 18.10.2012 (प्रति संलग्न) जारी की है जिसके अनुसार :-

1. यदि पट्टा विलेख स्वयं छातेदार के पक्ष में अधवा पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्टाम्प इयूटी 500/- लप्ये देय होगी।
2. यदि पट्टा विलेख दिनांक 30.09.2012 तक निष्पादित अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से उभार्कित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियम शुल्क, लपातारण शुल्क, विकास शुल्क बाज़, पेनल्टी राशि एवं दो वर्ष की प्रशालित दर से स्टाम्प इयूटी देय होगी।"

अतः संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1(vi) के अन्तिग पैरा, जिसमें यह बताया गया था कि मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की गणना नियमन शुल्क की चार गुण राशि के आधार पर की जायेगी, को विलोपित समझा जावें तथा मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की गणना वित्त विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 18.10.2012 के अनुसार ही नहीं।

2. प्रव्र में जारी पट्टो का पंजीयन :-

संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1(viii) के अन्तर्गत दताया गया है कि जिन प्रकरणों में भू-राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 90 वी के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर भूखण्डों का नियमन कर पट्टे मय स्टाम्प शुल्क जारी किये जा चुके हैं किन्तु इन पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं करवाया गया है उन पट्टों के नवीनीकरण की कार्यवाही की जाकर सामाज्य आवासीय प्रीनियम पर पर अभियान के दोरान शिविरों में पंजीयन करवाने की व्यवस्था की जायेगी। अगर पूर्व में पट्टा-विलेख स्टाम्प पेपर पर जारी किये जा चुके हैं तो पूर्ण मुद्रांकित पट्टों को नगर निकाय द्वारा रिवेलिडेट किया जायेगा और ऐसे पट्टों को रिवेलिडेशन की तारीख से निष्पादित मानते हुए पंजीयन करवाया जा सकेगा। पंजीयन की कार्यवाही दिनांक 31.03.2013 तक की जा सकेगी। उक्त छूट के लिये पट्टों के पंजीयन हेतु आवेदन शिविर अवधि में किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्तानुसार रिवेलिडेट किये गये या पुनः निष्पादित किये गये पट्टों पर स्टाम्प शुल्क वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12-72 दिनांक 18.10.2012 (प्रति संलग्न), के अन्तर्गत निम्नानुसार देय होगा :-

3. उपरोक्त निकायों के द्वारा नियमित/आवंतित शुल्कों के संबंध में निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन अधिनियम 1958 की धारा 29 अंतर्गत के अनुसार नियमित 8 लाठ की अवधि में पंजीयन कराकर उपरोक्त निकाय द्वारा पूर्ण तर्फ पुक निष्पादित करवा कर दिनांक 31.03.2013 तक निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, लपातारण शुल्क, विकास शुल्क, बाज़, पेनल्टी की राशि को प्रतिफल भान्तते हुए कर्वने से स्टाम्प इयूटी की प्रशालित दर से स्टाम्प इयूटी देय होगी।"

(31)

३ दिनांक 17.06.09 के पूर्व अस्तित्व में आई विभिन्न योजनाओं के नियमन हेतु पूर्व के कैम्पों में जिन भूखण्डों के पट्टे जारी नहीं हुये उनके पट्टे जारी करने की प्रक्रिया :—

संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1(ix) के अन्तर्गत बताया गया है कि दिनांक 17.06.09 के पूर्व अस्तित्व में आई विभिन्न योजनाओं के नियमन हेतु पूर्व में आयोजित कैम्पों के दौरान कतिपय कारणों से पट्टे जारी नहीं हो सके थे। प्रथम नियमन कैम्प में जारी पट्टे पर सामान्य नियमन दर के आधार पर नियमन शुल्क वसूल किया जाता है तथा प्रथम कैम्प के उपरान्त नियमन शुल्क पर प्रथम कैम्प की दिनांक से ५०-प्रतिशत व्याज वसूल किया जाता है; अतः अभियान के दौरान कैम्पों को प्रथम कैम्प मानते हुए केवल सामान्य प्रीमियम दर के आधार पर प्रीमियम राशि वसूल करने हेतु संदर्भित पत्र से निर्देश दिये गये हैं।

वित्त विभाग ने ऐसे मामलों में मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की गणना/देयता के संबंध में अधिसूचना क्रमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12-72 दिनांक 18.10.2012(प्रति संलग्न) जारी की है। अतः तदनुसार कार्यवाही की जावे।

४. अभियान के दौरान पट्टा नहीं लेने पर अतिरिक्त राशि :—

संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1(x) के अन्तर्गत दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी आवासीय कॉलोनियों के संदर्भ में बताया गया है कि अभियान के दौरान आयोजित शिविर की अन्तिम दिनांक 31.03.2013 तक पट्टा नहीं लिये जाने की स्थिति में शिविर अवधि के पश्चात् नियमन किये जाने पर भूखण्डधारी से सामान्य नियमन (प्रीमियम) शुल्क से दोगुनी राशि शास्ति एवं व्याज के साथ वसूल की जायेगी।

वित्त विभाग द्वारा ऐसे मामलों में पृथक से आदेश जारी होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पट्टों पर स्टान्प शुल्क की छूट देय नहीं होगी।

५. पट्टे के पंजीयन पर मुद्रांक शुल्क बावत —

संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 11 में बताया गया है कि पट्टा विलेख निष्पादन हेतु अभियान के दौरान अवधि पार (time barred) दस्तावेजों को नगर निकाय द्वारा Revalidate कर पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर नियमन राशि पर ही मुद्रांक शुल्क देय होगा। यह छूट जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान आवासन मण्डल तथा समस्त स्थानीय निकायों द्वारा निष्पादित पट्टों पर दिनांक 31.03.2013 तक ही लागू होगी। यह छूट केवल उसी स्थिति में देय होगी जब इस निमित प्रार्थना पत्र शिविर अवधि तक आवेदक द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाए।

वित्त विभाग ने ऐसे मामलों में मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की गणना/देयता के संबंध में अधिसूचना क्रमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12-73 दिनांक 18.10.2012(प्रति संलग्न) जारी की है जिसके अनुसार :—

(310)

(32)

1. विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं उन पर सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा व्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के लिए में ली गयी कुल राशि पर कन्वेन्स की दर से देय होगी।
2. विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह पश्चात एवं घार माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं उन पर सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा व्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के लिए में ली गयी कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से देय होगी।
3. विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से घार माह पश्चात एवं आठ माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं उन पर सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा व्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के लिए में ली गयी कुल राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से देय होगी।

अधिसूचना में वर्णित संस्थाओं द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में अब तक पट्टे न्या निष्पादन ही नहीं हुआ हो तो अब पट्टा निष्पादित होने पर भी अधिसूचना क्रमांक एक 2(80)एक.जी./टैक्स/12-74 दिनांक 18.10. 2012 के तहत निम्नानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा :-

1. विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से दो माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा व्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के लिए में ली गयी कुल राशि की दर से देय होगी।
2. विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से दो माह पश्चात एवं घार माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा व्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के लिए में ली गयी कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से देय होगी;
3. विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से घार माह पश्चात एवं आठ माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत होने पर सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा व्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के लिए में ली गयी कुल राशि की दर से देय होगी।

(3:1)

6. राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना
पत्रों के रालोंगा शपथ पत्र को स्टाम्प शुल्क रो गुक्ता किये जाने वाले :-

(23)

राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के अन्तर्गत राजस्थान
नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा एवं
आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भू उपयोग परिवर्तन अनुज्ञा हेतु नियम 4 के उप
नियम (1) या नियमितिकरण के लिये नियम 16 यो उप नियम (1) के अधीन प्रस्तुत
आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्राप्त किये जाने का प्रायधान है। वित्त विभाग की
अधिसूचना क्रमांक एफ.2(70)/वित्त/12-75 दिनांक 18.10.2012 के द्वारा प्रशासन
शहरों के संग अभियान 2012 के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले ऐसे शपथ पत्रों पर
देय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई हैं। अतः अभियान के दौरान प्राप्त आवेदन
पत्रों के संलग्न शपथ-पत्र, स्टाम्प ड्यूटी के बिना भी स्वीकार्य होंगे, लेकिन
शपथ-पत्र विधिवत् सत्त्वापित् होना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मवदीय,

(जी.सिंहसिंह)
प्रमुख शासन सचिव-निविदि

क्रमांक: प.3(54)निविदि / 03 / 2011

जयपुर, दिनांक: 13.10.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त सम्बागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेजटर, राजस्थान।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. महापौर/समाप्ति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
10. इसने उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, निविदि।
11. रक्षित पत्रावली।


(आर.सी.पारिख)
उप शासन सचिव-द्वितीय

(312)

(34)

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक: 18.10.2012

राजस्थान रटाम्प अधिनियम, 1998 (1998 की धारा 9 की उप-पारा (1) हारा 100 वाकियों आ प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना छेदांक ए.2(२०)एफ.डी./टैक्स/ ००-१२४ द्वारा देती है कि राजस्थान सूत्रसंधार यह शब्द होने पर कि लंकाहेत में ऐसा किया जाना अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नदर निगम, नियमों के अन्तर्गत आवंटन या नियमन उपरान्त जारी पट्टों का पंजीयन दिनांक 31.03.2013 से जराने वाली है।

1. यदि पट्टा विलेख रखने वाले दाता के पक्ष में अध्या पूर्ण मुद्राकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्टाम्प ब्यूटी 500/- रुपये देय होगी।
2. यदि पट्टा विलेख दिनांक 30.09.2012 तक निष्पादित अद्वाकित या अपर्याप्त रूप से मुद्राकित दरभारणों ये अध्या पद लीज ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रुपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, व्याज पैनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औरत किराये की राशि को प्रतिफल मानते हुए कर्डेन्स पर स्टाम्प ब्यूटी की प्रथसित दर से स्टाम्प ब्यूटी देय होगी।
3. उपरोक्त निकायों के हारा नियमित/आधिकृत भूखण्डों के संबंध में निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 23 व 25 के अनुसार नियरिति ८(आँठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों से पुनर्वैध एवं पुनर्नियमित करायकर दिनांक 31.03.2013 तक पंजीयन देतु प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विलेख/लिखत पर स्थानीय निकायों की देय राशि यथा नियमन शुल्क, रुपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, व्याज, पैनल्टी की राशि को प्रतिफल मानते हुए कर्डेन्स पर स्टाम्प ब्यूटी देय होगी।

(सं.एफ.२(६०)एफ.डी./टैक्स/ १२-७२)
राज्यपाल के आदेश से।

(आदित्य पारीक)

शाकन उप सचिव, वित्त (कर)

प्राधिनियम नियामित की सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अधीक्षक, राम्प क्लॉडीय बुद्धालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग ५ (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी सभ विल नियामन की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. सुव्यवस्त्री (वित्त) नहोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख नारान सचिव, नारीय विकास आयोजन एवं रायपत्र शासन विभाग।
5. गहनिरीकाक, पंजीयन एवं शुद्धाक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आयोजन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्थायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. नियो लाइब्रे, प्रमुख शासन लाइब्रे, वित्त।
11. नियो लाइब्रे, प्रमुख शासन लाइब्रे, वित्त।
12. नियो लाइब्रे, शासन लाइब्रे, वित्त (प्रायर)।
13. निदेशक, धन समर्पण नियामित, राजस्थान, जयपुर।
14. सिस्टम एनाक्सिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सेक्षन), विभाग।
15. राजन उप सचिव

(313)

साजारथान सरकार
प्रिति (फर) विभाग
अधिसूचना

जयपुर, दिनांक: 18.10.2012

35

राजस्थान रस्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम नं. 14) ने धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शासनों का प्रयोग करते हुए तथा इस प्रियांक की अधिसूचना कमांड प-2(36)पिल्ट/कर/2010-60 दिनांक 19.08.2010 के अधिकारित करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना सभीचीन है, तरददारा आदेश दिया है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राथेकरण, जोधपुर विकास प्राथेकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, कृषि उष्ण वन्यजीवी एवं मरुदी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सहकार के किसी अन्य निकाय/उपकरण द्वारा आवश्यित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा विभागित लिमिटेड/सिलसर पंजीयन के लिए निम्नांकित सम्पुष्चालित अर्थात् निष्पादन को विकांक से ३ (तीन) माह की अवधि में पंजीयन कराकर उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/एकाउंट्स से पुनर्वैध एवं उपकरणित जारीकर दिनांक 31.03.2013 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे वित्तेखों या लिखतों पर देय-स्टाम्प-ब्यूटी पटाकर सम्पत्ति के ऊजार गृह्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगा:-

	पिवरण	देय स्टाम्प इयूटी
1	2	3
1.	विलेख/लिखत जो पुनर्वं एवं पुनः नियादन की दिनांक से दो माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपचम द्वारा व्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (पदि कोई हो) आदि की राशि को समिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि पर कर्चेन्स की दर से।
2.	विलेख/लिखत जो नियादन की दिनांक से दो माह पश्चात एवं दोर माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपचम द्वारा व्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (पदि कोई हो) आदि की राशि को समिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कर्चेन्स की दर से।
3.	विलेख/लिखत जो पुनर्वं एवं पुनः नियादन की दिनांक से घार माह पश्चात एवं आठ माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपचम द्वारा व्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (पदि कोई हो) आदि की राशि को समिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कर्चेन्स की दर से।

(कृ.पंच.२(८०)पंक.जी. / टेक्स्ट / १२-७३)
राज्यपाल के आदेश से

(आदित्य नारीक) -

प्रतिलिपि निर्माणित को संधनाधर्ष पर्व अवधारणा कार्यसाधी देते थे।

- अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय नूदगिलव, जयपुर को असाधरण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियाँ इस विभाग को तथा 20 प्रतियाँ महानिरीक्षक, पंजीयन एवं नुटांक विभाग, राजस्थान अजमेर के समय वित्र मिजवाने की व्यवस्था करावे।
 - मनुष्य समिति, ना. नुटांकनगौ (हिन्दी) मठोबद्य।
 - महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
 - मनुष्य शासन समिति, नारायण विकास आवासन एवं स्थायता शासन विभाग।
 - महानिरीक्षक, पंजीयन एवं नुटांक विभाग, राजस्थान अजमेर;
 - आमुकत, जयपुर विकास प्रायोकरण, राजस्थान, जयपुर।
 - आमुकत जैशपुर विकास प्रायोकरण, राजस्थान, जैशपुर।
 - आमुकत, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
 - निदेशक, स्थायता शासन मिशन, राजस्थान, जयपुर।
 - निजी समिति, मनुष्य शासन समिति, निजि।
 - निजी समिति, मनुष्य शासन समिति, निजि।
 - निजी समिति, शासन समिति, निजि (राजस्थान)।
 - निकेक्षक, जग संस्कृत मिशनलर, राजस्थान, जयपुर।
 - स्टेट एकाडमीट, विद्या (कम्प्यूटर सी.डी.) विभाग।
 - क्लिंट प्रायोगिकी।

गासन उप संधिक

G314

36

राजस्थान सरकार
वित्त (फर) विभाग

अधिसंधन।

जयपुर. दिनांक: 18.10.2012

राजस्थान स्टाप्प अधिनियम् 1998 (1999) का अधिनियम भ. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त आलोचना का प्रयोग शर्ते हुए तथा इन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(36)वित्त/कर/2010-11 दिनांक 18.08.2010 वाले अधिकारित करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि ज्ञानकेन्द्र में ऐसा किया जाना सभीं द्वारा है, एतदद्वारा अद्वैत वाली है कि राज्य सरकार राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, भागर निगम, भावर वालिका, भागर परिवद, नगर संचार चारों के उपर एवं एवं नवजीवी समिति, ग्राम पंचायत, बंकारी आवासन संघ या शाप्त विभागों के विकास एवं विनियोजन विभाग द्वारा ज्ञानकेन्द्र में संबंधित सम्पत्ति के संबंध में बनाये जाने वाले अधिकार विभाग के अधिकार के किसी अन्य निकट/उपक्रम द्वारा ज्ञानकेन्द्र/विकास की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में बनाये जाने वाले अधिकार के किसी अन्य विभाग/सिवायों पर देय स्टाप्प ब्यूटी पटाकर दिया। 31.03.2013 तक सम्पत्ति के वाजार मूल्य के बाहर, पर निम्न प्रकार देय होगी:-

विवरण	देय स्टाम्प इंडस्ट्री
2 निलेख / लिखत निष्पादन की दिनांक में 2 माह की अधिकि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर। निलेख / लिखत निष्पादन की दिनांक में 2 माह पश्चात एवं 4 माह की अधिकि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	2 सरकार / स्थानीय निकाय / उपकरण द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यादे कोई हो) आदि की राशि को समिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ती गई कुल राशि की दो तिहाई राशि पर कर्नेन्स द्वारा दर से। 3 सरकार / स्थानीय निकाय / उपकरण द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यादे कोई हो) आदि की राशि को समिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ती गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि हरकार / स्थानीय निकाय / उपकरण द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यादे कोई हो) आदि की राशि को समिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ती गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कर्नेन्स की दर से।

(सं.एफ.2(८०)एफ.ओ. / ट्रेस / १२-७४)
राज्यपाल के आदेश के

(आदित्य पाराक)
रासन उप सधिय, वित्त (क्र.)

प्रोत्तिका नियमित को

- राजन उप संचिय, वित्त (कर)

 - अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, गंजीयन एवं मुद्राक विभाग, राजस्थान अजमेर को मध्य विल विभावने की व्यवस्था कराये।
 - प्रमुख संचिय, ना. बुद्धगंगेश्वी (विल) बहादूर।
 - महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
 - प्रमुख शासन संचिय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
 - महानिरीक्षक, धनरीय विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
 - आमुल, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
 - आमुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जोधपुर।
 - आमुक्त, राजस्थान आवासन बड़बद, राजस्थान, जयपुर।
 - निर्दिष्ट, प्रमुख शासन संचिय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - निर्जी संचिय, प्रमुख शासन संचिय, विभि।
 - निर्जी संचिय, शासन संचिय, विभि (राजस्थान)।
 - निर्वाचक, धनरीय विकास आवासन बड़बद, जयपुर।
 - विभाग इकाईविभाग, विभि (कम्प्यूटर सेवा) विभाग।
 - विभित प्रावित्ती।

भारत उप संघिं

(3 15)